epaper
हिन्दुस्तान

उद्योगों को जमीन मिलना आसान

18/05/2022

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने व आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए उसकी मैपिंग कराई जाएगी। इसमें वन क्षेत्र से लेकर सड़क व ग्राम सभा की जमीन तक शामिल है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति अभियान के तहत बने पोर्टल में इन सबका डेटा लोड किया जाएगा। इसके जरिए सभी विकास परियोजनाओं के लिए कार्ययोजना बनाने में सुविधा होगी। साथ ही जमीन आसानी से उपलब्ध होगी।

हाल में यूपी सरकार ने तय किया है कि 10 विभाग अपनी सारी अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था गतिशक्ति एनपी पोर्टल से लिंक करेंगे। साथ ही इस ही इस पोर्टल पर यूपी के शहरी इलाकों में जलापूर्ति, पाइपलाइन, सीवर लाइन व ड्रेनेज के लिए मैपिंग करा कर उसकी जानकारी साझा की जाएगी। प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों व पुरातत्व महत्व के स्थलों की भी मैपिंग कराई जाएगी।

मानचित्र अब ग्राम तक प्रदर्शित होगा: राज्य का प्रशासनिक मानचित्र अब ग्राम व भूखंड स्तर तक विकसित व एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए तहसील स्तर के भूसंपत्ति व खसरा स्तर के मानचित्रों को सैटेलाइट सुपर इम्पोज कर मास्टर मैप तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में 10 जिलों की एक-एक तहसील को लिया जाएगा। अभी तक राजस्व विभाग तहसील स्तर तक जीआईएस सीमाओं को अपडेट करता है। सिंचाई विभाग नहरों, जलस्रोतों, बारिश, बाढ़ की स्थिति का डेटा पोर्टल पर अपलोड करेगा।

इनको जिम्मा : ऊर्जा, पर्यटन, आवास, सिंचाई, नगर विकास, राजस्व, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन , भूतत्व खनिकर्म व कृषि।

पीएम गतिशक्ति

10 विभागों को सौंपा गया डेटा अपलोड का जिम्मा

- परियोजनाओं के लिए कार्ययोजना बनाने में आसानी होगी
- पोर्टल पर सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी

एक्सप्रेस वे, हाईवे और सड़कों की होगी मैपिंग

लोकनिर्माण विभाग व यूपीडा के साथ मिलकर एक्सप्रेसवे, हाईवे व अन्य सड़कों की मैपिंग कर उसके आंकड़ों को अपलोड करेगा। पुलों पर लोडिंग क्षमता का आकंडा होने से भारी लदे ट्रक के लिए उपयुक्त मार्गों का सुझाव दिया जा सकता है। पर्यावरण के नजरिए से ताज ट्रेपेजियम जोन, प्रदूषणकारी औद्योगिक कलस्टर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आंकड़े भी लिए जाएंगे। राज्य में 734 नगर हैं। इनमें से केवल 59 नगरों के लिए अमृत सिटी मास्टर प्लानिंग के लिए जीआईएस मैपिंग शुरू हो गई है। बाकी में जल्द काम शुरू कराया जाएगा। ऊर्जा विभाग गति शक्ति पोर्टल पर विद्युत पारेषण व वितरण के स्तर को अपडेट करने के लिए उत्तरादायी होगा।